

भारत में एक साथ चुनाव

परलिमिस के लिये: [केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक साथ चुनाव, लोकसभा, राज्य विधानसभाएँ, एक राष्ट्र, एक चुनाव, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, भारत नरिवाचन आयोग, राज्य नरिवाचन आयोग, ईवीएम, VVPATs, वधिआयोग, आदर्श आचार संहिता](#)

मेन्स के लिये: एक साथ चुनावों की आवश्यकता और संबंधित चर्चाएँ।

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

[16वें वित्त आयोग](#) के अध्यक्ष अरवि पनगढ़िया ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से सुधारों में बाधा आती है साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि [एक साथ चुनाव](#) कराने से शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार होता है।

एक साथ चुनाव का तात्पर्य क्या है?

- **वषिय: एक साथ चुनाव (एक राष्ट्र, एक चुनाव)** का तात्पर्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर करने से है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में एक ही दिन मतदान होगा, चुनाव कई चरणों में भी हो सकते हैं।
 - पहले चार चुनाव के दौरान (1952-1967), लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन बाद में संसद और विधानसभाओं के बार-बार समय से पहले भंग होने से यह चक्र बाधित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप चुनावों में देरी हुई।
 - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को प्रभावी बनाने के लिये एक साथ चुनाव संबंधी उच्च-स्तरीय समिति, 2023 की सफारिशों के [बादसंवधान \(129वाँ संशोधन\) वधियक, 2024](#) और [केंद्र शासति प्रदेश कानून \(संशोधन\) वधियक, 2024](#) पेश किये गए।
 - दोनों वधियकों को वसितृत जाँच के लिये संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है।
- **वधियक के मुख्य प्रावधान:**
 - **संवधान (129वाँ) संशोधन वधियक, 2024:** यह वधियक [अनुच्छेद 82A](#) को शामिल करता है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एकसमान किया जा सके। यह चुनाव आयोग (ECI) को **एक साथ चुनाव कराने का अधिकार** तथा चुनाव कार्यक्रम घोषित करते समय प्रत्येक राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि तय करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - वधियक में [अनुच्छेद 83](#) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार यदि लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो जाती है, तो अगली लोकसभा केवल शेष बचे कार्यकाल के लिये ही चलेगी।
 - इसी प्रकार के संशोधन [अनुच्छेद 172](#) में भी प्रस्तावित है, जो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है।
 - **केंद्रशासति प्रदेश कानून (संशोधन) वधियक, 2024:** यह वधियक **केंद्रशासति प्रदेश शासन अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली शासन अधिनियम, 1991 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ताकि केंद्रशासति प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप किया जा सके।
 - प्रस्तावित वधियक में [स्थानीय नकियाँ \(नगरपालिकाओं और पंचायतों\)](#) को शामिल नहीं किया गया है।

एक साथ चुनाव पर उच्च-स्तरीय समिति, 2023

- पूरे राष्ट्रपति रामनाथ कोव्दि की अध्यक्षता वाली समिति ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने का चक्र बहाल करने का प्रस्ताव रखा, पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराया जाए और उसके बाद 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनावों को एक साथ कराया जाए।
- इसने सफारिश की कि चुनावों को एक साथ कराने के लिये, राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक को "नयित तथि" घोषित करेंगे। इस तथिके बाद नरिवाचति राज्य विधानसभाएँ अगले संसदीय चुनावों तक ही कार्य करेंगी, जिससे भवषिय में एक साथ चुनाव सुनिश्चित होंगे।
 - **तरशिकु सदन या अवशिवास प्रस्ताव** जैसे मामलों में, शेष कार्यकाल के लिये नए सरि से चुनाव कराए जाएँगे।
- इसने एक साथ चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये **चुनाव आयोग और राज्य चुनाव नकियाँ** द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की

गई एकल मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र प्रणाली का भी आह्वान किया ।

भारत में बार-बार होने वाले चुनाव शासन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

- **नीतगित दबाव:** केंद्र सरकार सुधारों में देरी कर सकती है क्योंकि उसे आने वाले राज्य चुनावों में राजनीतिक नुकसान का डर होता है ।
- **परियोजना कार्यान्वयन में बाधा:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की **आदर्श आचार संहिता (MCC)** चुनावी अवधि में खरीद, परियोजनाओं के कार्यान्वयन और नीतगित फैसलों पर रोक लगा देती है ।
- **अल्पकालिक राजकोषीय फोकस:** सरकारें दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने के बजाय चुनाव जीतने के लिये **लोकलुभावन खर्च और सब्सिडी** पर ध्यान केंद्रित करती हैं ।
 - पाँच वर्षों के दौरान चुनावी चक्र राजकोषीय दबाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे संसाधनों का असमान आवंटन होता है ।
- **पहचान की राजनीति और सामाजिक विखंडन:** बार-बार होने वाले चुनाव **जाति, वर्ग या धर्म आधारित पहचान की राजनीति** को गतिप्रदान करते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन गहरा तथा दीर्घकालिक राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है ।
- **प्रशासनिक बाधाएँ:** वित्त आयोग जैसी परामर्शी और प्रशासनिक गतिविधियाँ चुनावों के दौरान बाधित या विलंबित हो सकती हैं ।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी में कमी:** लगातार चुनाव होने से मतदाताओं में **थकान (voter fatigue)** उत्पन्न होती है, जिससे उनका उत्साह घटता है और मतदान प्रतिशत में कमी आती है । इसका परिणाम यह होता है कि **लोकतांत्रिक भागीदारी की गुणवत्ता और समावेशिता** प्रभावित होती है ।

भारत में एक साथ चुनाव की क्या आवश्यकता है?

- **शासन में स्थिरता को बढ़ावा देना है:** चुनाव प्रचार से हटकर **विकासात्मक गतिविधियाँ और नीति कार्यान्वयन** पर ध्यान केंद्रित होता है । एक साथ चुनाव, कई चुनाव चक्रों से जुड़े व्यय को कम कर देते हैं, जिससे संसाधन **आर्थिक विकास** के लिये नशुलक हो जाते हैं ।
- **नीतिपक्षपात को रोकना है:** **आदर्श आचार संहिता (MCC)** के लंबे समय तक पालन को कम करता है और सरकारों को नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन तथा शासन में बेहतर नरितरता सुनिश्चित करने की अनुमति देता है ।
 - पार्टियों को नरितर चुनावों के बजाय **जनकल्याण के कार्यों** पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलाता है ।
- **संसाधनों के वचिलन को कम करना:** मतदान अधिकारियों और सविलि सेवकों की बार-बार तैनाती को सीमित करना तथा उन्हें मुख्य कर्तव्यों के लिये मुक्त करना ।
- **राजनीतिक अवसरों में वृद्धि:** एक साथ चुनाव कराने से सभी स्तरों पर अधिक उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, जिससे नए नेताओं को उभरने का अवसर मिलाता है और कुछ बड़े नामों का प्रभुत्व कम होता है, साथ ही पार्टियों के भीतर समावेशिता एवं व्यापक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलाता है ।

भारत में एक साथ चुनाव कराने पर समिति/आयोग की सफारिशें

- **भारतीय चुनाव आयोग (1983):** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव कराने की सफारिश की ।
- **वधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999):** दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने के तरीके सुझाए गए ।
- **वधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2015):** लागत बचत और सुचारू शासन का हवाला देते हुए इस विचार का समर्थन किया । राजनीतिक सहमति और क्रमिक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया ।
- **वधि आयोग की मसौदा रिपोर्ट (2018):** मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और दो चरणों में समन्वित चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

एक साथ चुनाव से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **लॉजिस्टिक भार:** एक साथ **96 करोड़ से अधिक मतदाताओं** के लिये चुनाव कराना मतलब **1 मिलियन से अधिक मतदान केंद्रों** का प्रबंधन करना, वशाल सुरक्षा बलों की व्यवस्था करना और अभूतपूर्व स्तर पर कार्मिकों की तैनाती करना होगा ।
 - मतदाता सूची को अद्यतन करना, कार्मचारियों को प्रशिक्षित करना, सुरक्षा का समन्वय करना और सभी राज्यों में एक साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाना अत्यंत जटिल कार्य होगा ।
- **प्रौद्योगिकी अवसंरचना:** केवल वर्ष 2024 के चुनावों में ही **1.7 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVMs)** और **1.8 मिलियन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलस (VVPATs)** का उपयोग किया गया । एक साथ चुनाव कराने के लिये इससे भी अधिक मशीनों, बैकअप और पूरी तरह सुरक्षित प्रणालियों की आवश्यकता होगी ।
- **संघीय चिंताएँ:** चुनाव चक्रों के सामंजस्य हेतु राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना, **संवैधानिक संघीय मूल भावना को आहत कर सकता है** ।
- **जवाबदेही:** चुनावों की आवृत्त घटने से सरकारों और नेताओं की जवाबदेही पर जनता का नरितरण कम हो सकता है ।
- **कानूनी अनश्चितता:** संशोधनों और नई प्रक्रियाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिससे कार्यान्वयन में देरी या जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं ।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** छोटे राज्यों और क्षेत्रीय पार्टियों को बड़े 'राष्ट्रीयकृत' चुनावों में नज़रअंदाज किये जाने का भय होता है ।

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. राष्ट्रीय वधि निर्माता के रूप में व्यक्तिगत सांसद की भूमिका में कमी आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप बहस की गुणवत्ता एवं परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न: "भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली, शासन का प्रभावी उपकरण सिद्ध नहीं हुई है।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए इस स्थिति में सुधार हेतु उपाय बताइये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/simultaneous-elections-in-india-1>

